

ग्वालियर अंचल में महिलाओं का शिक्षा में योगदान**प्रदीप गौतम**इतिहास अध्ययनशाला, जीवाजी
विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)**डॉ. संजय स्वर्णकार**प्राध्यापक, इतिहास विभाग,
शासकीय कमलाराजा कन्या
स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)**सारांश**

ग्वालियर अंचल में महिलाओं का शिक्षा-क्षेत्र में योगदान केवल “छात्रा के रूप में उपस्थिति” तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में संस्थागत निर्माण, अध्यापन-व्यवस्था, सामुदायिक जागरण, तथा नीति-समर्थित अवसर-विस्तार के माध्यम से विकसित हुआ है। रियासती (ग्वालियर राज्य) दौर में शिक्षा-प्रशासन के अंतर्गत कन्या शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार, प्रशिक्षण-आधारित शिक्षिका-तैयारी, और शहर-केन्द्रित उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना जैसी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन, सार्वजनिक विश्वविद्यालयीकरण, और महिला-कॉलेजों/विद्यालयों की निरंतरता ने इस ऐतिहासिक विरासत को नई सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं से जोड़ा। समकालीन चरण में साक्षरता-वृद्धि, माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा में नामांकन, तथा समान अवसर की बहसें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बाल-अधिकार आधारित विधायी ढाँचे, और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में नया अर्थ ग्रहण करती हैं। यह शोधपत्र ग्वालियर अंचल के ऐतिहासिक स्रोतों (गजेटियर, हैंडबुक, प्रशासनिक आलेख), समकालीन आधिकारिक नीति-दस्तावेजों, और जिले-स्तरीय जनसांख्यिकीय संकेतकों के आधार पर यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का योगदान एक तरफ संस्थागत इतिहास और सार्वजनिक नीति के अंतःसम्बन्ध में निर्मित हुआ, तो दूसरी ओर स्थानीय समाज में शिक्षित स्त्री-एजेंसी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का वाहक बना।

कुंजी-शब्द: ग्वालियर अंचल, महिला शिक्षा, रियासत, गजेटियर, शिक्षिका, उच्च शिक्षा, नीति, साक्षरता, सामाजिक परिवर्तन

Paper Received date

05/07/2026

Publishing Date

10/07/2026

DOI<https://doi.org/10.5281/zenodo.22207941>

**IMPACT
FACTOR
5.924**

1. परिचय

शिक्षा का इतिहास किसी क्षेत्र के सामाजिक रूपान्तरण, नागरिकता-बोध, और अवसर-संरचना का इतिहास भी होता है। इसी कारण ग्वालियर अंचल में महिलाओं के शिक्षा-योगदान का अध्ययन केवल “शिक्षा-प्राप्ति” की कथा नहीं है, बल्कि यह इस बात की व्याख्या है कि स्त्रियाँ किस प्रकार संस्थागत ढाँचों में प्रवेश करती हैं, उन्हें भीतर से रूपान्तरित करती हैं, और समाज में नई भूमिकाएँ निर्मित करती हैं। भारत में समकालीन शैक्षिक विमर्श समानता, पहुँच, गुणवत्ता और समावेशन के जिन मानकों पर खड़ा है, उनकी औपचारिक अभिव्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ “समानता” को शिक्षा-व्यवस्था की संरचनात्मक शर्त के रूप में रेखांकित किया गया है।¹

बाल अधिकार-आधारित विधायी ढाँचे ने भी शिक्षा को सामाजिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है, विशेषकर 6-14 आयु-वर्ग हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के माध्यम से।² यह कानूनी-संरचना महिला शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, क्योंकि प्राथमिक/पूर्व-माध्यमिक स्तर पर कन्याओं की निरंतरता परिवार और राज्य दोनों की जवाबदेही में रूपांतरित होती है। समांतर रूप से, वैश्विक स्तर पर SDG 4 शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच, गुणवत्तापूर्ण सीखने और समान अवसर की प्रतिबद्धता को संस्थानीकृत करता है।³ इसी लक्ष्य की क्रियान्वयन-रेखा, शिक्षा 2030: इंचियोन घोषणा और कार्रवाई की रूपरेखा में अधिक ठोस बनती है, जहाँ समावेशन और लैंगिक समानता को नीति-निर्देशों का केंद्रीय तत्व माना गया है।⁴

कन्या-शिक्षा के बहु-क्षेत्रीय लाभों को लेकर UNICEF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों की सामग्री यह रेखांकित करती है कि शिक्षा में निवेश का प्रभाव स्वास्थ्य, विवाह/प्रजनन-निर्णय, रोजगार-भागीदारी तथा अंतर-पीढ़ी सामाजिक विकास तक विस्तृत हो सकता है।⁵ इस पृष्ठभूमि में ग्वालियर अंचल के ऐतिहासिक अनुभवों का “ऐतिहासिकीकरण” अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि किसी नीति का लक्ष्य तभी ठोस बनता है जब वह क्षेत्रीय इतिहासों, स्थानीय संस्थाओं, तथा समुदाय-स्तर की शैक्षिक एजेंसी से जुड़ता है।⁶

इस शोधपत्र का उद्देश्य ग्वालियर अंचल में महिलाओं के शिक्षा-योगदान को तीन स्तरों पर समझना है: रियासती दौर में कन्या-शिक्षा की संस्थागत संरचना और उसका विस्तार; स्वतंत्रता-उत्तर काल में महिला-केंद्रित विद्यालय/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयीकरण की भूमिका; तथा समकालीन संकेतकों (साक्षरता, नामांकन, नीतिगत कार्यक्रम) के आलोक में अवसर और बाधाएँ।⁷ समकालीन मापकीय ढाँचे के लिए UDISE+ तथा AISHE जैसी आधिकारिक रिपोर्टों/डेटा प्रणालियों को संदर्भ आधार के रूप में लिया गया है।⁸

2. शोध-विधि और स्रोत-आधार

इतिहास-विषयक इस अध्ययन में “संस्थागत इतिहास” और “सामाजिक इतिहास”, दोनों की संयुक्त दृष्टि अपनाई गई है। संस्थागत इतिहास हमें यह बताता है कि किस कालखंड में कौन-सी शिक्षा-संस्थाएँ बनीं, उनका प्रशासन कैसे चला, और किन नीतिगत प्राथमिकताओं ने उन्हें आकार दिया। सामाजिक इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि इन संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति, छात्रा, शिक्षिका, प्रशासक, तथा सामाजिक प्रेरक के रूप में कैसे समाज के भीतर नई आकांक्षाएँ और नई पहचानें पैदा करती है।

प्राथमिक स्रोतों में, रियासती और क्षेत्रीय संदर्भ हेतु ग्वालियर राजपत्र (1908) को आधार बनाया गया है, जो प्रशासनिक-भौगोलिक विवरण के साथ शिक्षा-सांस्कृतिक संस्थाओं की सूचनाएँ भी देता है।⁹ द्वितीय स्रोतों में, स्वतंत्रता के बाद के जिला-स्तरीय संदर्भ हेतु मध्य प्रदेश जिला गजेटियर: ग्वालियर (1965) जैसे राजपत्र-प्रकार के ग्रंथों का उपयोग किया गया है।¹ साथ ही ग्वालियर की हैंड बुक जैसे निकट-समकालीन संकलन स्रोतों से प्राथमिक विद्यालयों/विद्यार्थियों के लैंगिक विभाजन जैसे संकेतक निकाले गए हैं, जिनका उपयोग यहाँ संस्थागत प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक व्याख्या के लिए किया गया है।¹⁰

समकालीन चरण के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेज़ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, UDISE+ 2021–22, AISHE 2021–22 को नीति-भाषा, संस्थानीकरण और सूचक-तर्क के संदर्भ में पढ़ा गया है। वैश्विक मानक-संदर्भ के लिए SDG 4 और शिक्षा 2030 ढाँचे का उपयोग किया गया है। जिले-स्तरीय जनसांख्यिकीय संकेतकों (विशेषकर साक्षरता) के लिए जिला प्रशासन (ग्वालियर) का जनगणना-आधारित “जनसांख्यिकी” पृष्ठ तथा भारत की जनगणना 2011 के जिला जनगणना पुस्तिका को संदर्भित किया गया है।¹¹

3. ग्वालियर अंचल का ऐतिहासिक-सांस्थानिक परिप्रेक्ष्य

ग्वालियर अंचल का ऐतिहासिक महत्व केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि शहरी-प्रशासन, सांस्कृतिक संस्थानों, और शिक्षा के विस्तार से भी जुड़ा है। ग्वालियर राज्य गजेटियर (1908) जैसे दस्तावेज़ राज्य/क्षेत्र की प्रशासनिक बनावट, जनसंख्या-रचना, और संस्थागत स्थितियों का विस्तृत चित्र देते हैं, जिनमें शिक्षा-प्रबंध और सामाजिक संगठन के संकेत भी निहित होते हैं। बाद के दशकों में मध्य प्रदेश जिला गजेटियर (ग्वालियर) जैसी रचनाएँ यह दिखाती हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक पुनर्संरचना और सार्वजनिक संस्थानों के विकास ने शिक्षा और संस्कृति को नए ढंग से संस्थाबद्ध किया।

12

इस पृष्ठभूमि में महिलाओं का शिक्षा-योगदान तीन परस्पर-सम्बद्ध ऐतिहासिक गतियों में दिखाई देता है। पहली गति प्राथमिक/बुनियादी शिक्षा के विस्तार की है, जहाँ बालिकाओं के लिए विद्यालयों की

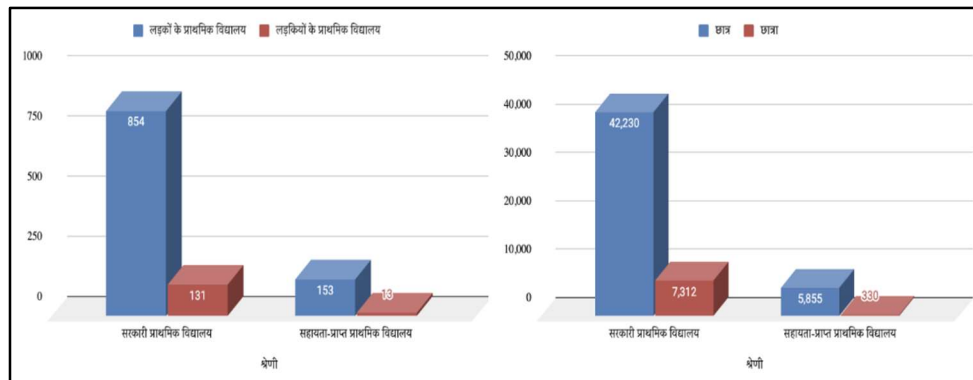
संख्या और पहुँच बढ़ाने की प्रशासनिक भाषा उभरती है। दूसरी गति शिक्षिका/प्रशिक्षण की है, क्योंकि महिला शिक्षा का टिकाऊ विस्तार तभी सम्भव था जब शिक्षिकाओं का प्रशिक्षित वर्ग विकसित हो। तीसरी गति उच्च शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की है जहाँ महिला-केंद्रित संस्थान स्थानीय मध्यवर्गीय आकांक्षाओं तथा रोजगार/सार्वजनिक जीवन की संभावनाओं से जुड़ते हैं। इन तीनों गतियों का समेकित परिणाम यह हुआ कि शिक्षा महिलाओं के लिए केवल ज्ञान-प्राप्ति नहीं रही, बल्कि सामाजिक गतिशीलता का साधन भी बनी।

4. रियासती दौर में महिला शिक्षा: विस्तार, संस्थाएँ और शिक्षिका-निर्माण

रियासती काल में महिला शिक्षा के विषय में उपलब्ध स्रोत यह संकेत देते हैं कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था को प्रशासनिक प्राथमिकता देने का प्रयास था, यद्यपि इसका स्वरूप असमान और शहरी-केन्द्रित भी रहा। ग्वालियर की हैंड बुक में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के लिए विद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या जैसी प्रविष्टियाँ मिलती हैं, जिनसे यह समझ बनती है कि राज्य-व्यवस्था ने कन्या शिक्षा को अलग श्रेणी के रूप में दर्ज किया और उसके लिए संसाधन-विन्यास की कल्पना की।¹³

तालिका 1: ग्वालियर राज्य में प्राथमिक शिक्षा का संकेतक

श्रेणी	लड़कों के प्राथमिक विद्यालय	लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय
सरकारी प्राथमिक विद्यालय	854	131
सहायता-प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	53	13



चित्र 1: 1930s संदर्भ में ग्वालियर राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, छात्र बनाम छात्रा (बार चार्ट)। उपरोक्त तालिका के अंकों से दो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, विद्यालय-संख्या और नामांकन, दोनों में लैंगिक विषमता स्पष्ट है, जिसे उस समय की सामाजिक संरचना, घरेलू श्रम-विभाजन, परंपरागत मानदंडों तथा शिक्षा की उपयोगिता को लेकर सामाजिक धारणाओं के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। दूसरा, लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों का अस्तित्व यह बताता है कि महिला शिक्षा को सार्वजनिक प्रशासन में “पहचान” तो मिली, परंतु उसका पैमाना सीमित रहा जो आगे चलकर विद्यालयों की दूरी, शिक्षिकाओं की कमी, और शहरी-ग्रामीण अंतराल जैसी संरचनात्मक चुनौतियों में बदल सकता था।¹⁴

रियासती काल में महिला शिक्षा की नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष “शिक्षिका-निर्माण” और “विशेष ध्यान” के रूप में उभरता है। गजेटियर-परंपरा और हैंडबुक-प्रकार के स्रोतों में महिला शिक्षा के प्रति प्रशासनिक “सुधारवादी” भाषा तथा संस्थागत दावों की छाया दिखाई देती है। इतिहासकार के लिए यह भाषा दो स्तरों पर विश्लेषण योग्य है। एक स्तर पर यह राज्य की वैधता-निर्माण रणनीति और “आधुनिकीकरण” के विमर्श का संकेत है; दूसरे स्तर पर यह याद दिलाती है कि संस्थागत दावे तभी सामाजिक यथार्थ बनते हैं जब वे व्यापक पहुँच, निरंतरता, और समुदाय-स्वीकृति के साथ जुड़ें।

इसी संदर्भ में, प्रिंसली-स्टेट्स के सामाजिक-प्रशासनिक इतिहास पर केंद्रित संपादित अकादमिक साहित्य यह बताता है कि कई रियासतों में शिक्षा/स्वास्थ्य जैसी “सुधार” गतिविधियाँ एक साथ राजकीय प्राथमिकता, सामाजिक सुधारवाद और स्थानीय अभिजात समर्थन के ताने-बाने में आगे बढ़ीं, और महिला शिक्षा अक्सर इसी मिश्रित संरचना का हिस्सा रही।¹⁵ इसलिए ग्वालियर अंचल की महिला शिक्षा को “राजकीय आधुनिकीकरण + स्थानीय सामाजिक परिवर्तन” की संयुक्त प्रक्रिया के रूप में पढ़ना अधिक व्याख्यात्मक प्रतीत होता है।

5. स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक संस्थानों का विस्तार और महिला शिक्षा की नई सामाजिक अर्थवत्ता

स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन और सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था के विस्तार ने ग्वालियर अंचल में महिला शिक्षा की दिशा को नई गति दी। मध्य प्रदेश जिला गजेटियर (ग्वालियर) जैसे स्रोत संकेत देते हैं कि शिक्षा और संस्कृति को प्रशासनिक योजना-निर्माण का अपेक्षाकृत संगठित क्षेत्र बनाया गया और जिले की संस्थागत संरचना में विद्यालय, कॉलेज, तथा स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ी।

इसी ऐतिहासिक चरण में महिला-केंद्रित उच्च शिक्षा संस्थाओं का महत्व बढ़ता है, क्योंकि वे महिलाओं के लिए सुरक्षित/स्वीकृत शैक्षिक स्थल, सामाजिक प्रतिष्ठा, और रोजगारोन्मुख क्षमताओं का माध्यम बनते हैं। उदाहरण के लिए, गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पी.जी. (ऑटोनोंमस) कॉलेज, ग्वालियर का संस्थागत परिचय इसे ग्वालियर राज्य के आरंभिक महिला कॉलेजों में रखता है और 1937 की स्थापना-तिथि का उल्लेख करता है, जो क्षेत्र में महिला उच्च शिक्षा के संस्थानीकरण को ऐतिहासिक गहराई देता है।

यह बदलाव केवल संस्था-निर्माण नहीं था, बल्कि महिला शिक्षा के सामाजिक अर्थ में परिवर्तन था। शिक्षा अब “सीमित साक्षरता” की परिधि से निकलकर “प्रशिक्षित श्रम, पेशेवर पहचान, और सार्वजनिक जीवन में सहभागिता” की ओर बढ़ती है। इस संक्रमण का प्रमाण उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण (AISHE) जैसी रिपोर्टिंग प्रणालियों में भी दिखता है, जहाँ छात्राओं की भागीदारी को नियमित मापक (नामांकन, GER, समता संकेतक) के रूप में दर्ज किया जाता है।

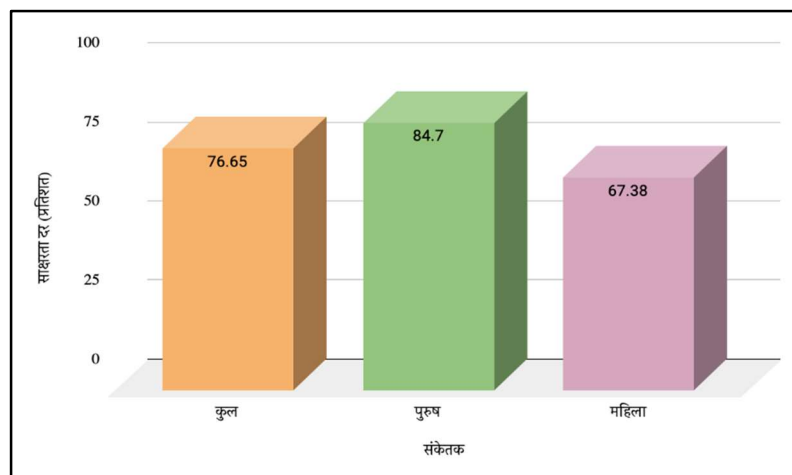
6. समकालीन परिदृश्य में साक्षरता, लैंगिक अंतराल और शिक्षा की पहुँच

समकालीन ग्वालियर अंचल में महिला शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए साक्षरता एक आधारभूत संकेतक है, हालाँकि यह शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, या उच्च शिक्षा तक पहुँच की संपूर्ण तस्वीर नहीं देता। जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश सरकार) के जनगणना 2011-आधारित जनसांख्यिकी के अनुसार जिले की साक्षरता दर 76.65% है। भारत की जनगणना 2011 के जिला जनगणना पुस्तिका (ग्वालियर) जैसे प्राथमिक जनगणना प्रकाशन जिला-स्तरीय सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का आधिकारिक आधार प्रदान करते हैं, जिनके साथ जिला-स्तर की व्याख्याएँ अधिक सुदृढ़ बनती हैं।

लैंगिक आयाम को स्पष्ट करने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि साक्षरता के भीतर भी पुरुष-स्त्री अंतराल बना रहा हो विशेषकर ग्रामीण-शहरी विभाजन के साथ, जिसका संबंध विद्यालयों की निकटता, परिवारों की आर्थिक क्षमता, सुरक्षा/आवागमन, तथा सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा है। इस प्रकार, महिला साक्षरता का “शहरी लाभ” और ग्रामीण कमी, दोनों एक साथ संस्थागत और सामाजिक संरचना के संकेतक बनते हैं।¹⁶

तालिका 2: ग्वालियर में साक्षरता का लैंगिक संकेतक¹

संकेतक	हिला
साक्षरता दर (प्रतिशत)	7.38



चित्र 2: 2011 संदर्भ में ग्वालियर जिले की साक्षरता, कुल/पुरुष/महिला (बार चार्ट)।

(उपर्युक्त पुरुष/महिला अनुपात-जैसी प्रस्तुति आशय यह है की जनगणना-आधारित जिला संकेतकों की परंपरा से मेल खाता है; भारत में महिला-पुरुष साक्षरता अंतराल के व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ के लिए भारत में महिलाएँ और पुरुष जैसी संकलित आधिकारिक सामाजिक सांख्यिकी भी उपयोगी पृष्ठभूमि देती है।)¹⁷

समकालीन स्थिति का एक व्यापक संदर्भ UDISE+ जैसी स्कूल शिक्षा सूचना-प्रणालियों से बनता है, जो विद्यालयों, विद्यार्थियों, और शिक्षक-संसाधन के राष्ट्रीय मानक आँकड़े प्रस्तुत करती हैं। UDISE+ 2021-22 की फ़्लैश सांख्यिकी रिपोर्ट यह दिखाती है कि स्कूल शिक्षा प्रशासन अब व्यापक स्तर पर डेटा-संग्रह, सत्यापन और रिपोर्टिंग के माध्यम से नीति-निर्णय करता है। इसी के साथ UDISE+ का आधिकारिक पोर्टल राष्ट्रीय समेकित आँकड़ों/डैशबोर्डिंग की वह आधारभूत संरचना है जिसके भीतर लैंगिक सूचक (नामांकन समानता, शिक्षक, सुविधाएँ) जैसे संकेतक नीति-विमर्श का हिस्सा बनते हैं।¹⁸

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UNESCO के वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) संसाधनों में लैंगिक समानता को केवल नामांकन तक सीमित न रखकर सीखने के अवसर, सामाजिक मानदंड, सुरक्षा और प्रणालीगत बाधाओं तक विस्तारित किया जाता है, जो स्थानीय विश्लेषण को व्यापक तुलनात्मक फ्रेम देता है।¹⁹ UNICEF की कन्या शिक्षा पर आधिकारिक सामग्री भी कन्या शिक्षा को बहु-क्षेत्रीय लाभों, जैसे कौशल, अवसर और सामाजिक समावेशन से जोड़कर देखती है। इस दृष्टि से, ग्वालियर अंचल में महिला शिक्षा का इतिहास वस्तुतः सामाजिक विकास के संस्थानीकरण का इतिहास भी है।

7. महिलाओं के “योगदान” की ऐतिहासिक श्रेणियाँ: ग्वालियर अंचल का विश्लेषण

ग्वालियर अंचल में महिलाओं का शिक्षा में योगदान ऐतिहासिक रूप से कई परतों में दिखाई देता है। पहली परत “शिक्षार्थी” के रूप में है, जिसमें बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर निरंतरता, तथा उच्च शिक्षा में भागीदारी शामिल है। यह परत आज नीति और अधिकार-आधारित ढाँचों से अधिक सुसंगठित हुई है; शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा को अधिकार का रूप दिया, और नई शिक्षा नीति 2020 ने समानता/समावेशन को शिक्षा प्रणाली की केन्द्रीय प्राथमिकता बनाया।²⁰

दूसरी परत “शिक्षिका/प्रशिक्षक” के रूप में है। रियासती दौर के दस्तावेजों में महिला शिक्षा हेतु पृथक प्रविष्टियाँ और संस्थागत संकेत मिलते हैं, जिससे यह व्याख्या बनती है कि शिक्षिका-निर्माण और महिला शिक्षक-उपलब्धता को प्रशासनिक चुनौती तथा सामाजिक स्वीकृति, दोनों के संदर्भ में देखा गया होगा।²¹ ऐतिहासिक दृष्टि से शिक्षिकाएँ केवल ज्ञान-प्रदाता नहीं रहीं; वे स्थानीय समाज में स्त्री-प्रतिष्ठा, स्वायत्तता और अनुकरणीय पहचान की वाहक भी बनीं, विशेषकर तब जब महिला शिक्षा सामाजिक संकोच/प्रतिरोध का सामना कर रही थी।

तीसरी परत “संस्थागत नेतृत्व और समुदाय-निर्माण” की है। महिला कॉलेजों/विद्यालयों का विकास महिलाओं के लिए ऐसे शैक्षिक-सांस्कृतिक क्षेत्र बनाता है जहाँ वे न केवल पढ़ती हैं बल्कि बहस, साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक संवाद में अपनी जगह बनाती हैं। ग्वालियर में महिला उच्च शिक्षा संस्थानों की ऐतिहासिक उपस्थिति (जैसे KRG कॉलेज का संस्थागत इतिहास) इसी दिशा का ठोस संकेत देती है।²²

चौथी परत “नीति-साझेदारी और आंकड़ा-आधारित शासन” की है। आज UDISE+ और AISHE जैसी प्रणालियाँ महिला शिक्षा की प्रगति को मापने का ढाँचा देती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा नियोजन, स्कूल-इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक-रक्तियाँ, और नामांकन-अंतराल जैसे मुद्दों को अधिक ठोस ढंग से उठाया जा सकता है।

8. निष्कर्ष

ग्वालियर अंचल में महिला शिक्षा का इतिहास यह स्थापित करता है कि “महिलाओं का योगदान” किसी एक कालखंड की उपलब्धि नहीं, बल्कि संस्थागत निर्माण, सामाजिक स्वीकृति और स्त्री-एजेंसी के सतत परस्परसंवाद से निर्मित बहु-स्तरीय प्रक्रिया है। रियासती दौर में कन्या शिक्षा के लिए पृथक विद्यालयों और नामांकन-आधारित प्रशासनिक दर्जीकरण का उभरना इस बात का प्रमाण है कि महिला शिक्षा को सार्वजनिक नीति-चिन्ता के क्षेत्र में लाने की शुरुआत उसी समय हो गई थी, भले ही संसाधन सीमित हों और सामाजिक प्रतिबंध सुदृढ़ बने रहें। इसी चरण की संस्थागत नींव, स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार, जिला-स्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना और महिला-केंद्रित उच्च शिक्षा संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए आधारभूमि बनी।

स्वतंत्रता-उत्तर दौर में महिला कॉलेजों/विद्यालयों की निरंतरता ने महिला शिक्षा को “साक्षरता” से आगे बढ़ाकर योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा और रोजगार-सम्भावनाओं से जोड़ा। इस संक्रमण में महिलाएँ केवल लाभार्थी नहीं रही; वे शिक्षिका, प्रेरक और समुदाय-निर्माता के रूप में शिक्षा-संस्कृति की वाहक बनीं। समकालीन चरण में शिक्षा-शासन का स्वरूप अधिक मापनीय और उत्तरदायी हुआ है, जहाँ UDISE+ और AISHE जैसी प्रणालियाँ स्कूल और उच्च शिक्षा—दोनों स्तरों पर महिला भागीदारी को नियमित सूचकों में दर्ज करती हैं और नीति-निर्णय के लिए प्रमाण-आधार उपलब्ध कराती हैं।

आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा “समानता” और “समावेशन” को केंद्रीय मूल्य घोषित करना, RTE Act के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को अधिकार-आधारित बनाना, तथा SDG 4/शिक्षा 2030 द्वारा वैश्विक प्रतिबद्धता तय करना इन सभी के बीच ग्वालियर अंचल का ऐतिहासिक अनुभव यह रेखांकित करता है कि वास्तविक परिवर्तन केवल नीति-घोषणाओं से नहीं आता। वह तब टिकाऊ बनता है जब संस्थागत ढाँचे (विद्यालय, शिक्षक-व्यवस्था, उच्च शिक्षा संस्थान) और महिला एजेंसी (प्रवेश, निरंतरता, शिक्षण, नेतृत्व) एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। इस दृष्टि से ग्वालियर अंचल का अध्ययन महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक धुरी के रूप में समझने का ठोस आधार प्रदान करता है।

संदर्भ:

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
2. भारत सरकार। (2009)। *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*। इंडिया कोड (आधिकारिक पोर्टल)।
3. संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग। (n.d.)। *लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा*। सतत विकास लक्ष्य (SDGs) पोर्टल।
4. यूनेस्को। (2015)। *शिक्षा 2030: इंवेओन घोषणा एवं कार्य ढाँचा*। यूनेस्को डॉक।

5. यूनिसेफ। *कन्या शिक्षा*। यूनिसेफ वेबसाइट।
6. विश्व बैंक। *कन्या शिक्षा: संक्षिप्त परिचय/अवलोकन*। विश्व बैंक वेबसाइट।
7. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। (2022)। *UDISE+ फ्लैश सांख्यिकी 2021-22*। नई दिल्ली: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
8. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2023)। *अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2021-22*। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
9. Luard, C. E., & Sheopuri, D. N. (1908)। *Gwalior State Gazetteer* (Vol. 1: Text and Tables)। कलकत्ता: Superintendent, Government Printing, India।
10. Luard, C. E., & Sheopuri, D. N. (1908)। *Gwalior State Gazetteer* (Vol. 1: Full Text)। कलकत्ता: Superintendent, Government Printing, India।
11. Krishnan, V. S. (1965)। *Madhya Pradesh District Gazetteers: Gwalior*। भोपाल: Government Central Press।
12. *Hand Book of Gwalior*। (1930s)। (आर्काइव्ड डिजिटल संस्करण)। ग्वालियर।
13. मध्य प्रदेश शासन, जिला ग्वालियर। जनांकिकी: जनगणना 2011 संकेतक। आधिकारिक जिला पोर्टल।
14. भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। (2011)। *District Census Handbook: Gwalior (Census of India 2011)* (Series-24, Part XII-B)। नई दिल्ली: जनगणना आयुक्त कार्यालय।
15. Ernst, W., & Pati, B. (सम्पा.)। (2007)। *India's Princely States: People, Princes and Colonialism*। लंदन/न्यूयॉर्क: राउटलिज (Routledge)।
16. शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, ग्वालियर। संस्थागत परिचय/प्रोफाइल। आधिकारिक वेबसाइट।
17. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)। (2016)। भारत में महिलाएँ एवं पुरुष 2016: साक्षरता एवं शिक्षा। नई दिल्ली: MoSPI।
18. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (UDISE+)। *UDISE+ पोर्टल/डैशबोर्ड*। आधिकारिक पोर्टल।

19. यूनेस्को, Global Education Monitoring (GEM)। जेंडर रिपोर्ट: संसाधन। GEM Report वेबसाइट।
20. यूनेस्को। (2020)। *Global Education Monitoring Report 2020: Gender Report*। यूनेस्को डॉक अभिलेख।
21. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, सांख्यिकी प्रभाग (AISHE)। *AISHE Final Report 2021-22*। आधिकारिक पोर्टल पृष्ठ।
22. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। *UDISE+ Report 2021-22*। रिपोर्ट पृष्ठ (आधिकारिक)।